

प्रधानमंत्री-इलेक्ट्रिक बस सेवा

प्रलिस के लयल:

प्रधानमंत्री-इलेक्ट्रिक बस सेवा, [इलेक्ट्रिक बसें](#), सार्वजनिक-नजी भागीदारी, [ई-मोबिलिटी](#), नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, [ग्रीनहाउस गैस](#)

मेन्स के लयल:

प्रधानमंत्री-इलेक्ट्रिक बस सेवा, धारणीय गतशीलता और ग्रीनहाउस गैस कटौती में इसका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

भारतीय मंत्रिमंडल ने "पी.एम.ई-बस सेवा अथवा प्रधानमंत्री-इलेक्ट्रिक बस सेवा" योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य सार्वजनिक-नजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से 10,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करके शहरों में बसों के संचालन को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री-इलेक्ट्रिक बस सेवा:

- **परचिय:**
 - इसका उद्देश्य शहरी परविहन दक्षता में वृद्धि करना और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
- **खंड A: सटी बस सेवाओं में वृद्धि करना (169 cities):**
 - यह खंड सार्वजनिक-नजी भागीदारी मॉडल के तहत 10,000 ई-बसों द्वारा शहरी परविहन को सुदृढ़ करने हेतु समर्पित है।
 - यह योजना इलेक्ट्रिक बसों के प्रभावी संचालन के लिये इलेक्ट्रिक बसों हेतु सबस्टेशन जैसे महत्वपूर्ण वदियुत बुनियादी ढाँचे के निर्माण के अतिरिक्त बस डपि के बुनियादी ढाँचे के निर्माण अथवा उन्नयन की आवश्यकता को चहिनति करती है।
- **खंड B: हरति शहरी गतशीलता पहल [Green Urban Mobility Initiatives (181 शहर)]:**
 - इस खंड में बसों की प्राथमिकता बढ़ाना, बुनियादी ढाँचे में सुधार, मल्टीमॉडल इंटरचेंज सुवधिएँ उपलब्ध करना, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (National Common Mobility Card- NCMC)-बेसड ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सस्टिम लागू करना और आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है।
 - इस योजना का लक्ष्य इन टिकाऊ प्रथाओं को एकीकृत करके शहरी गतशीलता परदृश्य को बदलना है।
- **लक्षति जनसंख्या और पहुँच से वंचति क्षेत्र:**
 - यह योजना 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर तीन लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहरों को शामिल करेगी।
 - इस व्यापक दृष्टिकोण में केंद्रशासति प्रदेशों की सभी राजधानियाँ, देश के उत्तर पूर्वी हसिसे के क्षेत्र और पहाड़ी राज्य शामिल हैं।
 - इस योजना का एक महत्त्वपूर्ण आकर्षण संगठति बस सेवाओं की कमी वाले शहरों पर इसका ध्यान केंद्रति करना है तथा शहरी गतशीलता अंतर को कम करना है।
- **संचालन एवं सुवधि:**
 - इस योजना का परचालन पहलू, नयिकृत बस ऑपरेटरों को भुगतान करते समय बस सेवाओं को प्रबंधति करने तथा बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों और शहरों पर डालता है।
 - केंद्र सरकार की भूमिका योजना में उल्लखति सबसिडी प्रदान करके इन कार्यों को सुवधाजनक बनाना और इनका समर्थन करना है।

योजना का महत्त्व:

- **रोज़गार के अवसर:**
 - इस योजना से 45,000 से 55,000 लोगों के रोज़गार की अनुमानति सीमा के साथ प्रत्यक्ष रोज़गार अवसर बढ़ने का अनुमान है।
 - यह बढ़ावा सटी बस संचालन में इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती से होगा, जो शहरी गतशीलता की जरूरतों को पूरा करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देगा।
- **ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देना:**
 - यह [ई-मोबिलिटी](#) को अपना देने के लिये प्रेरति करती है, जो अपेक्षति मीटर के पीछे वदियुत के बुनियादी ढाँचे के लिये व्यापक समर्थन पर

आधारति है।

- इसके अलावा शहरों को [गरीन अरबन मोबिलिटी पहल](#) के हस्से के रूप में महत्त्वपूर्ण चार्जिंग के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये समर्थन प्राप्त होगा।
- यह समग्र दृष्टिकोण न केवल ऊर्जा-कुशल इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने में तेजी लाता है बल्कि ई-मोबिलिटी क्षेत्र में नवाचार को भी बढ़ावा देता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव और GHG में कमी:**
 - वदियुत गतशीलता की ओर बदलाव से बड़े पर्यावरणीय लाभ होने का अनुमान है।
 - ध्वनि और वायु प्रदूषण को कम करने के साथ कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाकर, यह योजना व्यापक स्थिरता लक्ष्यों को हासिल करेगी।
 - बस-आधारित सार्वजनिक परिवहन के बढ़ते उपयोग से भी एक बदलाव आएगा, जिससे [गरीनहाउस गैस \(GHG\) उत्सर्जन](#) में कमी आएगी।

ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिये सरकारी पहल:

- [इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और वनरिमाण करना \(FAME\) योजना II](#)
- [नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मशिन योजना \(NEMMP\)](#)
- [परिवर्तनकारी गतशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मशिन](#)
- [उत्पादन आधारित प्रोत्साहन \(PLI\) योजना](#)
- [वाहन सकरैपेज नीति](#)
- [गो इलेक्ट्रिक अभियान](#)

आगे की राह

- "पी.एम.-ईबस सेवा" योजना टिकाऊ शहरी गतशीलता और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
- प्रत्यक्ष रोज़गार सृजन, बुनियादी ढाँचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण तक वसित अपने बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ, यह योजना लचीली एवं पर्यावरण-अनुकूल शहरी परिवहन प्रणाली बनाने के लिये भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करती है।
- इस दूरगामी सोच वाली रणनीति का शहरी विकास और पर्यावरण प्रबंधन दोनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

[स्रोत: द द्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pm-ebus-sewa>

